



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ ज्येष्ठ 3, 1940

No. 190]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/ JYAISTHA 3, 1940

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)**

**जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना**

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

**(निर्णायक समीक्षा)**

**विषय – चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पेरसिडामोल के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत**

**फा. सं. 7/16/2018-डीजीएडी.—** 1995 में तथा उसके बाद यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली कहा गया है) के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पेरसिडामोल” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को आगे लागू रखने के लिए सिफारिश की है।

1. यतः संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा 30 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 60/1/2000-डी जी ए डी द्वारा आरंभ की गई थी। प्रारंभिक जांच परिणामों को प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना सं. 60/1/2000-डीजीएडी द्वारा जारी किया गया था और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2001 की अधिसूचना सं. 89/2001-सीमाशुल्क के अनुसार लागू किया गया था। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं. 60/1/2001 के अनुसार लागू किया गया था। अंतिम निर्णायक समीक्षा संबंधी अधिसूचना

प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं. 60/1/2000-डीजीएडी के अनुसार जारी की गई थी जिसके अनुसार निर्धारित शुल्क को लागू करने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. 29/2002-सीमाशुल्क के अनुसार निश्चित पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था। पहली निर्णायक समीक्षा समाप्त की गई और प्राधिकारी ने दिनांक 23 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 15/20/2006-डी जी ए डी के अनुसार निर्णायक समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम जारी किए तथा दिनांक 3 सितंबर, 2007 की अधिसूचना सं. 99/2007-सीमाशुल्क के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लागू किया गया। द्वितीय निर्णायक समीक्षा समाप्त की गई तथा प्राधिकारी ने दिनांक 26 अगस्त, 2013 की अधिसूचना सं. 14/1009/2012-डी जी ए डी के अनुसार निर्णायक समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम जारी किए और दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. 26/2013-सीमाशुल्क के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लागू किया गया।

2. चूंकि, श्रीकृष्णा फार्मास्युटीकल्स लिमि., हैदराबाद और फार्मासन फार्मास्युटीकल गुजरात प्रा.लि., बडोदरा ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए, अधिनियम और नियमों के अनुसरण में, भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की ओर से, प्राधिकारी के समक्ष एक भली-भांति साक्ष्यांकित आवेदन दायर किया गया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने और उनकी समीक्षा के लिए अनुरोध किया है।

### **घरेलू उद्योग**

3. घरेलू उद्योग की ओर से निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन श्रीकृष्णा फार्मास्युटीकल्स लिमि., हैदराबाद और फार्मासन फार्मास्युटीकल गुजरात प्रा.लि., बडोदरा द्वारा दायर किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में प्रमुख समानुपात का उत्पादन करते हैं और इसलिए नियमावली के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग ठहरते हैं।

### **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

4. मूल के साथ ही वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "एसिटामिनोफेन के रूप में भी ज्ञात पैरासिटामोल" है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण जांच में मूल जांच में शामिल उत्पाद सम्मिलित हैं।

5. पैरासिटामोल एक गंधरहित सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। इसका रसायन फार्मूला  $C_8H_9NO_2$  है। पैरासिटामोल एक बल्क फार्मास्युटीकल सक्रिय घटक है जो एनाल्गेसिक और एंटी-प्रेटिक गुण प्रदर्शित करता है। यह पाउडर, कणिकाओं, इंजेक्शन योग्य और गोलियों के रूप में बड़ी संख्या में आरएक्स और ओटीसी दवा फार्मूलों में प्रयुक्त होता है। पैरासिटामोल एक जैविक रसायन है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 2922.2933 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

### **निर्णायक समीक्षा की शुरुआत**

6. यतः प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

**सम्मिलित देश**

7. इस जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

**जांच अवधि**

8. आवेदक द्वारा याचिका में जाँच अवधि (पीओआई) के रूप में 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि दी गई है। प्राधिकारी ने वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) भी 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 निर्धारित की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष अप्रैल, 14-मार्च, 15, अप्रैल 15-मार्च, 16, अप्रैल, 16-मार्च, 17 और पीओआई शामिल है।

**प्रक्रिया**

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 22 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं 60/1/2000-डीजीएडी और दिनांक 23 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं 15/20/2006-डीजीएडी के अनुसार प्रकाशित निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम और दिनांक 26 अगस्त, 2013 की अधिसूचना सं.14/1009/2012-डीजीएडी के अनुसार प्रकाशित निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम के अधीन यथा अधिसूचित सभी पहलू शामिल होंगे।

10. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

**सूचना प्रस्तुत करना**

11. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को पृथक् रूप से नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

**भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,  
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

12. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**समय-सीमा**

13. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

14. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।

16. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (05) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

17. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

18. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

19. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

20. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

21. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**असहयोग**

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**New Delhi, the 24<sup>th</sup> May, 2018**(Sunset Review )****Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Paracetamol, originating in or exported from China PR.**

**F. No. 7/16/2018- DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Paracetamol” (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

1) WHEREAS, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 60/1/2000 – DGAD dated 30<sup>th</sup> January, 2001. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. 60/1/2000-DGAD dated 16<sup>th</sup> April, 2001 and the provisional antidumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 89/2001 Customs dated 6<sup>th</sup> September, 2001. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No. 60/1/2000-DGAD dated 22nd January 2002, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed w.e.f 6<sup>th</sup> September, 2001 by the Department of Revenue vide Notifications No. 29/2002 Customs dated 27<sup>th</sup> March, 2002 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from the subject country. 1<sup>st</sup> Sunset Review concluded and Authority had issued the Final Findings in the Sunset Review vide Notification No. No. 15/20/2006-DGAD dated 23<sup>rd</sup> July 2007 and fixed duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 99/2007 -Customs dated 3<sup>rd</sup> Sept, 2007. 2nd Sunset Review concluded and Authority had issued the Final Findings in the Sunset Review vide Notification No. 14/1009/2012-DGAD –dated 26<sup>th</sup> August 2013 and fixed duty was imposed by the Central Government vide Notification No 26/2013-Customs dated 28 October, 2013.

2) Whereas, Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd, Hyderabad and Farmson Pharmaceutical Gujarat Pvt Ltd. Vadodara have filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods in India, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

**Domestic Industry**

3) The application for the sunset review has been filed by Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. Hyderabad and Farmson Pharmaceutical Gujarat Pvt Ltd. Vadodara, on behalf of the domestic industry. As per the information available, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

**Product under consideration and Like Article**

4) The product under consideration, in the original as well as the present sunset review investigation, is “Paracetamol also known as acetaminophen”, originating in or exported from China PR. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation.

5) Paracetamol is an odourless white crystalline powder. Its chemical formula is  $C_8H_9NO_2$ . Paracetamol is a bulk pharmaceutical active ingredient, displaying analgesic and antipyretic properties. It is used in a number of Rx and OTC drug formulations in the form of powders, granules, injectibles and tablets. Paracetamol is an organic chemical and is classified under custom sub-heading 2922.2933 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

#### **Initiation of Sunset Review**

6) WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

#### **Country involved**

7) The country involved in this investigation is China PR.

#### **Period of Investigation**

8) The petitioner has given the POI in the petition from 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March, 18. The Authority has also decided the Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March 2018. However, injury analysis shall cover the years Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16, Apr'16-Mar'17 and the POI.

#### **Procedure**

9) The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No.60/1/2000-DGAD dated 22<sup>nd</sup> January 2002, the Sunset review findings published vide Notification No. 15/20/2006-DGAD dated 23<sup>rd</sup> July 2007 and the Sunset Review findings published vide notification No. 14/1009/2012-DGAD dated 26 August,2013.

10) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

#### **Submission of Information**

11) The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,  
Directorate General of Trade Remedies,  
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building,  
5 Parliament Street, New Delhi -110001.

12) Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

13) Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

14) All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of information on confidential basis**

15) In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as NonConfidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16) Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

17) For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18) The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

19) The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20) Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file:**

21) In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

22) In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority